(b) A provision for setting up a radio station at Tura was included in the original shelf of schemes for the draft Fifth Plan. However, due to the paucity of financial resources, this provision could not be retained in the finalised version of the Fifth Plan. The area has been surveyed from the point of view of ascertaining the feasibility of setting up a radio station at this centre. Frequencies have also been coordinated internationally for the operation of medium-wave transmitters at Tura. Attempt will be made to include it in the 6th Plan proposals.

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये योजना

6033. **श्री बालक राम :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोगौलिक और जलवायु की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों के कृषि तथा औद्योगिक विकास हेतु देश के मैदानी क्षेत्रों के लिए बनाई गई योजनाओं से भिन्न योजना की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है और उससे हिमाचल प्रदेश कितनी मात्रा में लाभान्वित हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों वाली राज्य सरकारों या पूर्णत: पर्वतीय राज्यों से यह अनुरोध किया गया हैं कि कृषिक तथा अन्य विकास कार्यक्रम तैयार करते समय वे अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति, संसाधन प्रयास, आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था, आदि का ध्यान रखें ।

मुख्य उद्देश्य ये हैं कि कृषि, बागबानी, वनोद्योग और भूमि संरक्षण के विकास कार्य को व्यापक किया जा सके । अर्थ-व्यवस्था के कृषि तथा अन्योन्य क्षेत्रों के विकास में तीव्रता लाने के लिए बिजली, सिंचाई, सड़क, विपणन तथा ऋण से संबंधित बुनियादी आधारभूत सुविधाओं को बढाया जा सके । व्यापक विषमताओं को कम करने/समाप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा, पेयजल की पूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण स्वास्थ्य आदि से संबंधित कार्यक्रमों पर भी बल दिया गया है ।

पर्वतीय राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की प्रणाली अधिक उदार हैं । इस प्रणाली से हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर को भी लाभ मिलता है ।

जो राज्य आंशिक रूप से पर्वतीय हैं वे स्थानीय स्थलाकृति, कृषि-जलवायु की स्थिति और संसाधनों के अनुरूप अपने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग से उप योजनाएं तैयार करते हैं । इन उप योजनाओं को कार्यान्वित करने के उनके प्रयासों में सहयोग करने के लिए उन्हें विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

शिमला अथवा कसौली में दूरदर्शन केन्द्र

6064. **श्री बालक राम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के इलाकों के लिए शिमला अथवा कसौली में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरजोर मांग की है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए किन-किन मार्गदर्शी बातों का पालन किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवानी : (क) जी, हां ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कसौली में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।।

(ग) किसी दूरदर्शन केन्द्र के स्थापित करने में जिन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाता है वे है तकनीकी संभाव्यता और वित्तीय संसाधनों के अनुरूप अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करना।

Family Allowance to MISA Detenus in Tihar Jail

6035. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of political MISA detenus in Tihar Jail who moved High Court and or Government for grant of family maintenance allowance during emergency period;

(b) how many of them were not granted family allowance and the reasons therefor;

(c) whether Government propose to pay family allowance to such ex-MISA detenus of Delhi who were the sole bread earners for their families who were not earlier granted family allowances; and

(d) if so, by what time, and if not, reasons therefor ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) 84.

(b) to(d). According to the information furnished by the Delhi Administration, family allowance has been sanctioned in 28 cases. The remaining cases are being scrutinised by them and will be finalised soon.

Reinstatement of Central Government Employees

6036. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number and details of Central Government employees at Delhi detained under MISA during emergency with grounds of detention;

(b) number of those dismissed/removed while under detention and reasons therefor in each case ;

(c) whether all of them have since been reinstated and paid their dues;

(d) if not, reasons therefor and by what time they would be reinstated and paid their dues without break in service or treating them as on duty, and

(e) whether they would be paid full pay for the entire period without break in service, if so, when ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) According to the information received from the Delhi Administration 23 Central Government servants were detained under MISA at Delhi during the Emergency for the reasons indicated below :—

(1) Association with RSS	1
(2) Association with Anand Marg	1
(3) Association with CPI(M)	3
(4) Espionage.	1
(5) Activities prejudicial to public order	6
(6) Anti-national activities and malpractices . .	10
(7) Illegal foreign exchange activities	1

(b) to (e). Government have taken a decision and orders in this behalf have already been issued that all Central Government employees who were detained under MISA or removed /dismissed from service during the Emergency for their participation in the activities of the RSSS, the Jamaat-e-Islami, Anand Marg, CP (ML) and CPI (M) should be reinstated forthwith, that the period between the date of removal from service and the date of reinstatement and the period during which a Government servant remained under suspension due to this detention under MISA should be treated as on duty purposes of increment and pension and that he should be paid subsistence allowance for such period equal to 50% of the salary.

Government employees involved in espionage and other objectionable and illegal activities are not to be reinstated